

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2221/2011/हनुमानगढ़

सहायक आयुक्त,  
वृत्त बी, हनुमानगढ़

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नौलखा जिनिंग एण्ड ऑयल मिल,  
पीलीबंगा

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक  
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे ("अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 376/आरवेट/हनुमानगढ़ /09-10 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त हनुमानगढ़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु पारित आदेश दिनांक 25.03.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55, 58, 18, 4(2) के तहत कायम की गई मांग राशि रिवर्स टैक्स राशि रुपये 1,73,800/-, क्रय कर राशि रुपये 29,333/- व धारा 55 के तहत ब्याज राशि रुपये 54,846/- व शास्ति अन्तर्गत धारा 58 राशि रुपये 250/- को विवादित करने पर अपील आंशिक स्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स राशि रुपये 1,73,800/-, क्रय कर राशि रुपये 29,333/- व धारा 55 के तहत ब्याज राशि रुपये 54,846/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी रॉ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बिनौला तथा बिनौला से बिनौला तेल एवं खल का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों रूई, बिनौला तेल एवं खल बिनौला का प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य एवं अन्तर्राज्यीय में विक्रय करता है। निर्माण प्रक्रिया में कॉटन से रूई 35 प्रतिशत, तेल बिनौला 7.5 प्रतिशत तथा खल बिनौला 55 प्रतिशत वजनानुसार निर्मित होता है। खल बिनौला कीमत में 25 प्रतिशत होती है। प्रत्यर्थी ने रॉ कॉटन की स्थानीय खरीद पर शत-प्रतिशत इनपुट क्रेडिट का क्लेम किया है। प्रत्यर्थी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से नरमा, कपास खरीदकर उस

२०२

लगातार.....2

विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हुए रूई बिनौला तेल खल का निर्माण किया है एवं निर्मित माल रूई बिनौला तेल पर कर चुकाया है। परन्तु खल जो राज्य में कर मुक्त है उस पर कर नहीं चुकाया है। आरवैट एक्ट, 2003 की धारा -4(2) के अनुसार ऐसे बिक्रीत माल का उपयोग धारा-18(1) के उपबन्धों से भिन्न परियोजनाओं में किया गया है। अतः ऐसे माल पर क्रय कर का दायित्व बनता है, जो प्रत्यर्थी द्वारा नहीं चुकाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी पर क्रय कर रुपये 29,333/- एवं ब्याज आरोपित किया है तथा निर्मित बिनौला खल के कर मुक्त होने के कारण आनुपातिक आधार पर खरीदे गये कच्चे माल पर चुकाये गये कर के संबंध में व्यवहारी द्वारा लिये गये इनपुट क्रेडिट राशि रुपये 1,73,800/- रिवर्स किया है तथा ब्याज राशि रुपये 54,846/- आरोपित किया है व धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति राशि रुपये 250/- आरोपित की है। अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 27.01.2011 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स राशि रुपये 1,73,800/-, क्रय कर राशि रुपये 29,333/- व धारा 55 के तहत ब्याज राशि रुपये 54,846/- को अपास्त किया है जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में धान की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल छिलका की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व ब्याज अपास्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-

22

6. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद की गई रॉ कॉटन का उपयोग रूई, बिनौला, बिनौला तेल तथा बिनौला खल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें बिनौला खल कर मुक्त उत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वेट चुकाकर खरीदी गई उक्त रॉ कॉटन के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज का आरोपण किया गया है।

7. इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस. बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

8. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार किये जाने को विधिसम्मत ठहराया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा जिस न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर निर्णय पारित किया है वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर मुक्त माल पर आरोपित रिवर्स टैक्स एवं ब्याज अपास्त करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

२२

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.01.2011 को अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स राशि रुपये 1,73,800/-, क्रय कर राशि रुपये 29,333/- व धारा 55 के तहत ब्याज राशि रुपये 54,846/- को यथावत रखा जाता है।
10. निर्णय सुनाया गया।

(<sup>8/27</sup>नन्धूराम)  
सदस्य